PK टाइम्स

लोक टुडे

विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

pktimesnews.com
loktodaynews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk_timesofficial

वर्ष: 12 | अंक: 313 | मूल्य: 1.00 रुपए | पृष्ठ: 4 | शुक्रवार 29 मई 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

आंदोलन की आंच : भैराणा में झुकी सरकार

अब गिरल माइंस पर टिकी निगाहें

भैराणा धाम में आस्था की जीत के बाद अब सुलग रहा गिरल माइंस का मुद्दा

रोजी-रोटी के लिए तरसते मजदूर बोले - हमारा क्या कसूर?

लोक दुडे। जयपुर

राजस्थान की धरती पर इस समय दो बड़े आंदोलन जनता के बीच सबसे बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक तरफ जहां जयपुर के दूदू स्थित भैराणा धाम में संतों और आम जनता की ऐतिहासिक जीत हुई है, वहीं दूसरी तरफ बाड़मेर के शिव क्षेत्र में स्थित गिरल लिग्नाइट माइंस के मजदूर अपनी रोजी-रोटी के लिए महीनेभर से ज्यादा समय से भीषण गर्मी में धरने पर बैठे हैं। एक तरफ जीत का जश्न है, तो दूसरी तरफ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे गरीब मजदूरों की बेबसी का बड़ा सवालिया निशान। भैराणा धाम के संतों और आम जनता के संघर्ष की जीत से राजस्थान की सियासत गरमा गई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में हुई महापंचायत के बाद प्रशासन को झुकना पड़ा। सरकार द्वारा एक 'हाई पावर कमेटी' बनाने की सहमति के बाद जयपुर कूच का फैसला टल गया। वहीं इस बड़ी जीत के बीच पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित गिरल लिग्नाइट माइंस का मुद्दा सुलग रहा है। यहाँ के बेकसूर मजदूर पिछले 40 से अधिक दिनों से 45 डिग्री की भीषण गर्मी में अपनी रोजी-रोटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। संतों की जीत के बाद अब इन लाचार मजदूरों ने सरकार से सीधा सवाल पूछा है कि 'अगर आस्था की जीत हो सकती है, तो हमारे पेट की आग और रोजगार की इस लड़ाई पर सरकार चुप क्यों है? हमारा क्या कसूर है?

भैराणा धाम में जीती आस्था, 42 दिनों का संघर्ष लाया रंग :

जयपुर जिले के दूदू (बिचून) में स्थित 500 साल पुरानी दादू पंथ की पवित्र तपोस्थली भैराणा धाम को बचाने की जंग आखिरकार जनशक्ति की जीत के साथ संपन्न हुई। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO) द्वारा धाम के पास की करीब 850 बीघा वन भूमि को औद्योगिक क्षेत्र विस्तार के लिए अधिग्रहित किया जा रहा था, इसके लिए हजारों हरे-भरे पेड़ काट दिए गए, जिससे प्राकृतिक संतुलन और धार्मिक आस्था को गहरी ठेस पहुंची। भीषण गर्मी के बीच दादू पंथी संतों ने अपने चारों तरफ आग जलाकर 'अग्नि तप' किया और मांगें पूरी न होने पर जीवित समाधि लेने की कड़ी चेतावनी दी। जब आंदोलन के समर्थन में हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में लाखों लोगों का जनसैलाब महापंचायत में उमड़ा और जयपुर कूच का ऐलान हुआ, तो भजनलाल सरकार को तुरंत कदम उठाना पड़ा। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच सहमति बनी और इस पूरे भूमि विवाद की समीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। इसके बाद संतों ने अपना धरना समाप्त किया और जयपुर कूच को टाल दिया।

गिरल प्लांट आंदोलन : मजदूरों बोले - हमारा क्या कसूर, हक के लिए लड़ रहें :

भैराणा धाम की जीत के बीच, बाड़मेर के शिव इलाके में गिरल लिग्नाइट माइंस (RSMML) के बाहर स्थानीय मजदूरों का दर्दनाक आंदोलन लगातार जारी है। वहां मौजूद हर मजदूर के चेहरे पर एक ही सवाल है कि 'अगर संतों की आस्था की जीत हो सकती है, तो हमारे पेट की आग और रोजगार की मांग पर सरकार चुप क्यों है? हमारा क्या कसूर है?' स्थानीय ग्रामीणों और मजदूरों का आरोप है कि कंपनियों ने जमीन अधिग्रहण के समय स्थानीय लोगों को स्थाई रोजगार देने का वादा किया था। लेकिन अब ठेका कंपनियों द्वारा स्थानीय युवाओं और ड्राइवर्स को बिना किसी नोटिस के नौकरी से निकाला जा रहा है। मजदूर पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि श्रम कानूनों के तहत 8 घंटे की ड्यूटी लागू की जाए, न्यूनतम वेतन मिले और निकाले गए सभी कर्मचारियों को काम पर वापस रखा जाए। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी लगातार मजदूरों के साथ धरने पर डटे हुए हैं। प्रशासन की संवेदनहीनता के विरोध में उन्होंने बाड़मेर कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन भी तेज कर दिया है। मजदूरों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा शिव विधायक भाटी ने भी बाड़मेर कूच किया था। जहां उनके आत्मदाह का प्रयास करने के दौरान आंदोलन उग्र भी हुआ और प्रशासनिक स्तर पर वार्ताएं भी, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाली रही।

साधु-संत और क्षेत्रीय नेता दोनों आंदोलन की धुरी

भैराणा धाम में आस्था की जीत के बाद इस मुद्दे के और ज्यादा सुलगने की मुख्य वजह दोनों आंदोलनों का आपस में जुड़ाव और जन-समर्थन है।

साधु-संतों का समर्थन: भैराणा धाम के आंदोलन में जहां साधु-संतों ने भीषण गर्मी के बीच अपने चारों तरफ आग जलाकर 'अग्नि तप' किया और मांगें पूरी न होने पर जीवित समाधि लेने की कड़ी चेतावनी दी। वहीं विधायक रविंद्रसिंह भाटी और पीड़ित मजदूरों के आंदोलन को भी साधु-संतों ने अपना खुला समर्थन दिया है। संतों का कहना है कि सरकार को इस भीषण गर्मी में तपस्या कर रहे मजदूरों की बात सुननी ही होगी।

विपक्ष और क्षेत्रीय नेताओं की एंट्री : राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इस मुद्दे पर भाजपा की राज्य सरकार को घेरा है।
बेनीवाल ने जहां जयपुर के भैराणा में 'रीको भगाओ महापंचायत' का नेतृत्व किया, वहीं उन्होंने बाड़मेर में विधायक भाटी और मजदूरों के साथ हो रहे प्रशासनिक व्यवहार को लोकतंत्र पर कलंक बताया है।

आने वाले वर्षों में और गर्म होगी धरती, टूटेगा रिकॉर्ड

यूएन एजेंसी की चेतावनी, 2031 से पहले एक नया सबसे गर्म वर्ष दर्ज हो सकता है

नई दिल्ली

संयुक्त राष्ट्र की मौसम और जलवायु एजेंसी ने चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ वर्षों में गर्मी और बढ़ेगी। वैश्विक तापमान में पहले मुकाबले ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज होगी जिससे पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन की वर्तमान गति वैश्विक स्तर पर गंभीर प्रभाव डाल रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के अनुसार, 2015 के बाद से अब तक के सभी 11 सबसे गर्म वर्ष दर्ज किए गए हैं और यह प्रवृत्ति आगे भी जारी रहने की संभावना है। एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि 2031 से पहले एक नया सबसे गर्म वर्ष दर्ज हो सकता है। डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026

से 2030 के बीच वैश्विक औसत तापमान औद्योगिक युग से पहले (1850-1900) के स्तर से 1.3 से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है। इस बात की लगभग 75 प्रतिशत संभावना है कि इन पांच वर्षों का औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की महत्वपूर्ण सीमा को पार कर जाएगा। इसके अलावा, 91 प्रतिशत संभावना है कि 2026 से 2030 के बीच कम से कम एक वर्ष ऐसा होगा जब तापमान अस्थायी रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2026 के अंत में अल नीनो की स्थिति बनने की संभावना है, जिससे 2027 में नया तापमान रिकॉर्ड बनने का खतरा बढ़ सकता है। अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना है, जो प्रशांत महासागर के तापमान और वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित करती है। पिछले वर्षों में अल नीनो ने 2023 और 2024 को रिकॉर्ड गर्म वर्षों में बदलने में भूमिका निभाई थी। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि आने वाले वर्षों में आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत से कई गुना अधिक गर्म हो सकता है। इसके अलावा दुनिया के कई हिस्सों में बारिश और सूखे के पैटर्न में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पेरिस जलवायु समझौते के तहत तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है, हालांकि अस्थायी रूप से इसका पार होना अब अधिक संभव माना जा रहा है। रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती आने वाले समय में और गंभीर रूप ले सकती है, जिससे ऊर्जा नीति और वैश्विक पर्यावरण रणनीतियों पर दबाव बढ़ेगा।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बोले, 'हम गाय की रक्षा के लिए वोट देंगे'

फतेहपुर ।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ-रक्षा को लेकर कहा कि हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि गाय को पशु कहने वाली सरकार को हटाओ और गाय को माता कहने वाली सरकार लाओ। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि गाय की सुरक्षा को लेकर बात तो की जा रही है लेकिन उनकी गौ-भक्ति केवल मंचों और वक्तव्यों तक सीमित है। धरातल पर विपरीत स्थिति है। आश्रय स्थलों में गायों की हालत बहुत बुरी है। गौ तस्करों पर आज तक अंकुश नहीं लग पाया है। गायों के लिए कागजी काम हो रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जनता इनके प्रचार में आ जाती है। वास्तविक स्थिति दिखाई नहीं जाती। जो लोग गाय के बारे में सच्चाई बोल रहे हैं, उनके मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि पक्ष-विपक्ष राजनीति के लिए होता है। हमारे लिए कौन पक्ष है और कौन विपक्ष है? हमारे लिए जो सरकार बन गई, वही सरकार है। जनसंख्या को लेकर उन्होंने कहा कि

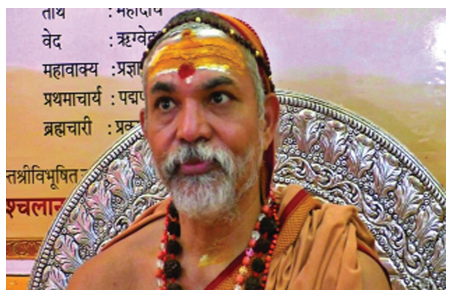

नेता इतने नाकाबिल हैं कि वे जनसंख्या के लिए काम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसलिए जनसंख्या उनको भार लग रही है। अगर वे काम ढूंढ पाते तो उनको बहुत अच्छा लगता कि हमारे पास काम करने वाले इतने लोग हैं। जनसंख्या जितना भगवान बढ़ाए, अच्छा है। उन्होंने कहा कि भाजपा आज गाय को राजमाता का दर्जा दे दे तो हम यात्रा बंद कर देंगे। हम गाय की रक्षा के लिए वोट देंगे ये तय है। सबको हम एक विकल्प दे रहे हैं, आपके पास ये विकल्प है। हमने भाजपा को वोट देकर गौ रक्षा के लिए सरकार बनाई है। हमारा वोट चाहिए उसको गाय को माता कहकर आना पड़ेगा।

बंगाल सरकार ने बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में बीएसएफ को 600 हेक्टेयर जमीन सौंपी: अमित शाह

गांधीनगर ।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में नवगठित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी के काम को मजबूत करने के लिए सात दिनों के भीतर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को 600 हेक्टेयर भूमि सौंप दी है। गांधीनगर जिले के सोनीपुर गांव में 340 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उ?द्घाटन और शिलान्यास समारोह के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने राज्य में सीमा पर बाड़ लगाने के काम में तेजी लाने के अपने चुनावी वादे को पूरा किया है। अमित शाह ने कहा, 'हमने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि यदि आप हमें सत्ता सौंपते हैं तो हम कुछ ही दिनों के भीतर बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर देंगे।' उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को बधाई देते हुए कहा, 'मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को महज सात दिनों के भीतर बीएसएफ को 600 हेक्टेयर भूमि सौंपने के लिए बधाई देना चाहता हूं। चिकन नेक क्षेत्र में 121 हेक्टेयर भूमि भी केंद्र सरकार को सौंप दी गई है।' अमित शाह ने इस कदम को भाजपा के व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडे से जोड़ा और दावा किया कि बंगाल में सरकार परिवर्तन के बाद बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ पहले ही कम हो गई है।

चहेतों को दी नौकरी, जांच रिपोर्ट में आरोप सही, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलगुरु को पद से हटाया

लोक दूडे । जयपुर

नियुक्तियों में भारी अनियमितताएं करने, धांधलियां कर चहेते अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने और विश्वविद्यालय नियम प्रावधानों को दरकिनार कर मनमाने तरीके से नियुक्तियां करने के मामले में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर कुलगुरु को पद से हटा दिया है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के प्रथम कुलगुरु और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलगुरु प्रो. देवस्वरूप को अपने पद से तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश राज्य सरकार के परामर्श से जारी किया गया है। बागडे को डॉ. देवस्वरूप द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए वर्ष 2011-2012 व चयन वर्ष 2013-14 के

चयन में जयपुर की डॉ. प्रेमलता सिंगारिया ने 'अनुसूचित जाति की महिला के साथ अन्याय' के अंतर्गत नियम-प्रावधानों को दरकिनार कर धांधली कर योग्य की बजाय चहेते अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की शिकायत की थी।

झूठे दस्तावेज रचे और अपने चहेतों को नियुक्ति दी -

राज्यपाल ने इस पर शिक्षाविद् और कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. भगवती प्रसाद सारस्वत की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की थी। जांच समिति ने डॉ. देवस्वरूप के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट पाया गया कि कुलपति रहते हुए डॉ. देवस्वरूप द्वारा नियम विरूद्ध, यूजीसी प्रावधानों को दरकिनार कर मनमाने तरीके से चयन संबंधित बैठकें आयोजित की गई, उनके मिनिट्स बनाए गए, सिंडिकेट की बैठकें आयोजित कर उनके प्रचलित पद्धति से हटकर मिनिट्स बनाते हुए कूटरचित, जाली और झूठे दस्तावेज रचे गए और चालाकी कर अपने चहेतों को नियुक्ति दी गई। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि शैक्षणिक रिकॉर्ड एवं शोध कार्य में डॉ. प्रेमलता सिंगारिया को पात्र होते हुए भी कम नंबर दिए गए। रिपोर्ट में

उच्च स्तरीय जांच समिति गठित, रिपोर्ट में माना दोषी -

रिपोर्ट के अंतर्गत डॉ. देवस्वरूप द्वारा योग्य अभ्यर्थियों के रिसर्च पेपर्स मूल्यांकन को नकारकर इंटरव्यू में मनमाने तरीके से शत-प्रतिशत अंक देकर चहेते अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना स्पष्ट सामने आया है। डॉ. देवस्वरूप द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर रहते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम-कानूनों को दरकिनार कर मनमाने तरीके से नियुक्तियां करने, आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग वर्ग के योग्य अभ्यर्थियों को उनके लिए बने नियमों, प्रावधानों की अनुपालना नहीं करने आदि में भी रिपोर्ट में दोषी पाया गया है।

अतिरिक्त कार्यभार आदेश -

राज्यपाल ने गुरुवार को ही आदेश जारी कर राजुवास, जोबनेर के कुलगुरु प्रो. (डॉ.) त्रिभुवन शर्मा को अपने कार्य के साथ-साथ बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद का और हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. (डॉ.) एन. के पाण्डेय को विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलगुरु का अतिरिक्त कार्यभार संभालने के आदेश दिए हैं।

मौखिक साक्षात्कार के आधार पर विषय ज्ञान एवं साक्षात्कार के निर्धारित अधिकतम 50 में से चहेतों को 49 नम्बर तक दिए गए और डॉ. प्रेमलता को महज 10 अंकों में ही नम्बर दिए गए।

सम्पादकीय

एसआईआर पर मुहर

अंततः सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर की चुनाव आयोग की प्रक्रिया को न केवल वैध करार दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उन विपक्षी नेताओं के लिए एक बड़ा झटका है, जो यह दुष्प्रचार करने में लगे हुए थे कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर एसआइआर के नाम पर मनमानी करने में लगा हुआ है। इस आदेश ने यह स्पष्ट किया कि झूठ के पैर नहीं होते और दुष्प्रचार के जरिये किसी वैध प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। इस पर हैरानी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से असहमत लोग निराशा व्यक्त कर रहे हैं। यह उनकी कुंठा के अतिरिक्त और कुछ नहीं, क्योंकि निष्पक्ष चुनावों की पहली शर्त ही यह है कि वैध मतदाता ही वोट डालें। कोई व्यक्ति वैध मतदाता है या नहीं, इसके निर्धारण के लिए आवश्यक छानबीन करना चुनाव आयोग का अधिकार है। यह विचित्र है कि कुछ विपक्षी दल चुनाव आयोग के इसी अधिकार को चुनौती देने के लिए ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगा रहे थे कि आयोग एसआइआर के बहाने उनके समर्थकों के वोट काटने का काम कर रहा है। ऐसे आरोप लगाने वालों ने यह स्पष्ट करने की जहमत कभी नहीं उठाई कि आखिर उन्हें कैसे पता चला कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, वे उनके वोटर हैं? बिहार में एसआइआर के दौरान जब करीब 65 लाख ऐसे नाम मतदाता सूची से हटाए गए, जो अन्यत्र बस गए थे या फिर जिनकी मृत्यु हो गई थी अथवा जिनके नाम दो जगह दर्ज थे तो यह शोर मचाया गया कि वैध मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, पर यह शोर मचाने वाले ऐसे 65 लोगों को भी नहीं जुटा सके। बिहार विधानसभा चुनावों में एसआइआर के कोई मुद्दा न बन पाने के बाद विपक्षी दलों और खासकर वोट चोरी का जुमला उछाल रही कांग्रेस को यह समझ आ जाना चाहिए था कि वह हारी हुई लड़ाई लड़ रही है, लेकिन न उसने दीवार पर लिखी इबारत पढ़ी और न ही अन्य विपक्षी दलों ने। विपक्षी दलों को इस पर खासी आपत्ति थी कि एसआइआर के तहत लोगों की नागरिकता की परख की जा रही है, जबकि चुनाव आयोग को ऐसा करने का अधिकार ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि चुनाव आयोग किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के क्रम में उसकी नागरिकता की जांच कर सकता है। आखिर इससे ही तो तय होगा कि वह भारत का वैध नागरिक है या नहीं? चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग की नागरिकता संबंधी जांच अंतिम फैसला नहीं मानी जाएगी, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि केंद्र सरकार लोगों की नागरिकता जांचने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी तैयार करने की दिशा में आगे बढ़े।

दुर्लभ खनिजों की नई वैश्विक जंग : भारत-अमेरिका समझौते के पीछे छिपा असली रणनीतिक खेल

भारत और अमेरिका ने जरूरी खनिजों एवं दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए अहम समझौते किए हैं, जिसमें उनका खनन और प्रसंस्करण भी शामिल है। इन समझौतों पर बीते मंगलवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका में उनके समकक्ष मार्को रूबियो ने हस्ताक्षर किए। रूबियो चार दिन की भारत यात्रा पर थे। उनकी इस यात्रा के आखिरी दिन 'क्वाड' (जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं) के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उसी दिन अलग से क्वाड देशों के बीच जरूरी खनिजों की आपूर्ति को लेकर एक रूपरेखा की घोषणा की। इसके साथ भारत के दुर्लभ एवं जरूरी खनिजों के भंडार के बारे में भी जानकारी साझा की गई। भारत-अमेरिका के बीच यह समझौता अहम हो सकता है, लेकिन इसमें परस्पर हितों का ख्याल रखा जाना बेहद जरूरी है।

एक कामयाब यात्रा का सेहरा बांध कर अमेरिका के विदेश मंत्री अपने वतन लौटे हैं। इस तरह अमेरिका ने क्वाड देशों के साथ चर्चा कर अपने लिए दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। यह बेहद महत्त्वपूर्ण है, लेकिन कई दृष्टि से विचारणीय भी है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी दस्तावेज में कहा गया कि क्वाड देशों की सरकारें और निजी कंपनियां इस पहल के लिए ऋण गारंटी, सब्सिडी और दीर्घकालिक खरीद समझौतों का उपयोग करते हुए बीस अरब डॉलर जुटाने का इरादा रखती हैं। इन देशों का उद्देश्य इस धन को खनन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण परियोजनाओं में लगाना है, ताकि महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति पर उनकी निर्भरता कम हो सके।

'दुर्लभ खनिज' क्या हैं और वे इतने महत्त्वपूर्ण क्यों हैं?-'दुर्लभ खनिज' क्या हैं और वे इतने महत्त्वपूर्ण क्यों हैं? इसका जवाब है कि ये ऐसे गैर-ईंधन खनिज हैं, जिनका उपयोग बैटरी, घड़ियां, वायरिंग, सैन्य हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर और अन्य तकनीकी उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। जरूरी खनिजों में 17 दुर्लभ खनिज तत्त्व शामिल हैं, जिनमें लैंथेनाइड (धात्विक तत्व), स्कैंडियम और यट्रियम की मांग सबसे अधिक है।

स्कैंडियम का उपयोग एयरोस्पेस और खेल उपकरण बनाने में किया जाता है। यट्रियम का उपयोग लेजर और सिरेमिक के निर्माण में होता है। लैंथेनाइड, उच्च तापमान वाले स्थायी चुंबक बनाने में इस्तेमाल होता है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और पवन चक्कियों के

काम आता है। गौरतलब है कि निकल, कोबाल्ट, लिथियम, एल्युमीनियम और जिंक सबसे जरूरी खनिजों में से हैं। अमेरिका बारह जरूरी खनिजों के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। वह 29 अन्य जरूरी खनिजों के लिए अपनी जरूरत का कम से कम आधा हिस्सा आयात करता है। उसकी आर्थिक या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी दुर्लभ खनिजों के आयात में कोई अड़चन न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका हरसंभव प्रयास कर रहा है।

दुर्लभ खनिजों का उपयोग हार्डवेयर के उन मुख्य घटकों में भी किया जाता है, जो सेमीकंडक्टर और कृत्रिम मेधा (एआई) तकनीकों में काम आते हैं। चीन के पास इनमें से बारह खनिजों के भंडार हैं। दुर्लभ खनिजों के प्रसंस्करण की लागत बहुत ज्यादा होती है और इनके खनन में भी भारी मात्रा में रसायनों का इस्तेमाल होता है, जिससे जहरीला कचरा पैदा होता है। फिलहाल, दुनिया में दुर्लभ खनिजों की ज्यादातर आपूर्ति पर चीन का नियंत्रण है। इन खनिजों का साठ फीसद हिस्सा चीन के पास है और वह दुनिया की कुल आपूर्ति का नब्बे फीसद हिस्से को उपयोग के लायक बनाता है। अमेरिका और दूसरे देश इन खनिजों के लिए चीन पर अधिक निर्भर हैं। अमेरिका ने खास तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए इन खनिजों के अन्य आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने पर जोर दिया है।

अब सवाल है कि भारत के पास कौन से दुर्लभ खनिज हैं? जुलाई, 2023 में भारत ने तीस खनिजों की एक सूची जारी की थी, जिसमें बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, तांबा, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नाइओबियम, निकल, प्लैटिनम समूह के तत्त्व, फास्फोरस, पोटाश के अलावा दुर्लभ मृदा तत्व- रेनियम, सिलिकान, स्ट्रोंटियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम का ब्योरा दिया गया था। बताया गया है कि भारत के पास एक करोड़ तीस लाख टन से ज्यादा मोनाजाइट है। यह एक फास्फेट खनिज है, जिसमें दुर्लभ ऑक्साइड होते हैं और यह दुर्लभ खनिजों के मुख्य प्राकृतिक स्रोतों में से एक है।

सरकार का अनुमान है कि देश के मोनाजाइट भंडार में सत्तर लाख टन से अधिक दुर्लभ मृदा ऑक्साइड (आरईओएस) मौजूद हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि चीन के भंडार में लगभग चार करोड़ चालीस लाख टन आरईओएस मौजूद है और यह दुनिया के ज्ञात भंडारों का लगभग आधा हिस्सा है। वर्ष 2026-2027 के बजट में सरकार ने ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 'दुर्लभ खनिज गलियारे' बनाने के लिए नए नीतिगत उपाय पेश किए हैं।

ये दुर्लभ खनिजों के खनन एवं प्रसंस्करण, अनुसंधान करने और इलेक्ट्रिक वाहनों, पवनचक्की तथा अन्य उन्नत तकनीकों में उपयोग होने वाले उच्च-प्रदर्शन वाले दुर्लभ चुंबकों के निर्माण के केंद्र होंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सब हमें खुद करना था या इसे किसी दूसरे देश के सुपुर्द करना था? इसमें दोराय नहीं कि अमेरिका सबसे पहले अपने हित देखता है। अगर क्वाड देश इसमें शामिल हैं, तो बहुपक्षीय सहमति के बावजूद केवल भारत और अमेरिका के बीच ही द्विपक्षीय समझौते पर जोर क्यों दिया गया? हाल में अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका में 'फलाबोर्वा रेयर अर्थ्स प्रोजेक्ट' में निवेश का एलान किया था। इससे पहले दिसंबर, 2025 में अमेरिका ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अहम खनिजों के खनन में 1.25 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी। फरवरी 2026 में उसने अहम खनिजों पर 'पैक्स सिलिका पहल' की थी, जिसमें उसने अर्जेंटीना, कुक आइलैंड्स, इक्वाडोर, गिनी, मोरक्को, पैराग्वे, पेरू, फिलीपींस, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और उज्बेकिस्तान के साथ अहम खनिजों से जुड़े ग्यारह समझौते किए थे।

अब भारत के दुर्लभ खनिज गलियारे पर भी उसकी नजर है। हालांकि, भारत का कहना है कि अमेरिका के साथ समझौते के जरिए दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति में सहयोग को और गहरा करना है। चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए अमेरिका ने जापान और भारत जैसे देशों के साथ अहम समझौते किए हैं।

बहरहाल, भारत के पास दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार है, जो उद्योगों के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करता है। देश के पास एक करोड़ तीस लाख टन से अधिक मोनाजाइट है, जिसमें अनुमानित सत्तर लाख टन से ज्यादा दुर्लभ ऑक्साइड शामिल हैं। ये भंडार ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड में पाए जाते हैं।

ये सभी भंडार मिल कर एक एकीकृत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना का समर्थन करने के लिए भारत के कच्चे माल के आधार को मजबूत करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि किसी भी देश से एकपक्षीय समझौते के बजाय परस्पर हितों को ध्यान में रखकर सहयोग की रणनीति तय की जाए।

सरकारी स्कूलों की आपराधिक उपेक्षा क्यों

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के एक लाख 19 हजार सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है; 98,592 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है; चौदह हजार से अधिक स्कूलों में पीने का पानी नहीं है; एक लाख से अधिक स्कूलों में सिर्फ एक अध्यापक एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ा रहा है। स्कूली शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में 'नीति' आयोग ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। यह विडंबना ही है कि 'नीट' की परीक्षा में हुई धांधली की धूल में नीति-आयोग की यह रिपोर्ट कहीं खो सी गयी है। इस रिपोर्ट के कुछ आंकड़े सिर्फ चौंकाते ही नहीं, परेशान भी करते हैं। जैसे, यह रिपोर्ट बताती है कि देश में सरकारी और निजी स्कूलों की स्थितियों का अंतर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की उपेक्षा को ही उजागर नहीं करता, बल्कि यह भी बता रहा है कि देश के भविष्य को लेकर हमारी चिंताएं कितनी खोखली हैं।

प्रधानमंत्री एक से अधिक अवसरों पर अपने भाषणों में इस आशय के दावे कर चुके हैं कि देश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास कर रहा है। मसलन, एक भाषण में उन्होंने कहा था कि देश में प्रति सप्ताह एक नया विश्वविद्यालय खुल रहा है, हर रोज एक नया कॉलेज खुल रहा है। प्रधानमंत्री आईआईटी और आईआईएम के विस्तार के दावे भी कर चुके हैं। लेकिन नीति-आयोग की यह रिपोर्ट शिक्षा क्षेत्र की बुनियादी कमजोरियों को उजागर कर रही है। पिछले

एक दशक के विश्लेषण पर आधारित यह रिपोर्ट बता रही है कि हमने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को सरकारी और गैर-सरकारी में बांटकर समूची शिक्षा प्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिये हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के एक लाख 19 हजार सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है; 98,592 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है; चौदह हजार से अधिक स्कूलों में पीने का पानी नहीं है; एक लाख से अधिक स्कूलों में सिर्फ एक अध्यापक एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ा रहा है। रिपोर्ट में ऐसे और भी कई आंकड़े हैं जो यह बताते हैं कि शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्र में हम किस तरह की आपराधिक उपेक्षा बरत रहे हैं। उदाहरण के लिए सन् 2017 और 2024 के बीच देश में 87000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो गये, इसकी तुलना में निजी स्कूलों की जैसे बाढ़-सी आ रही है।

यह सही है कि हाल के कुछ सालों में, विशेष कर कोरोना-काल के बाद सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वालों की संख्या कुछ बढ़ी है, पर इसका कारण शिक्षा का स्तर नहीं, अभिभावकों की आर्थिक विवशता कहीं अधिक है। वैसे, यह भी एक विडंबना ही है कि आज देश में हमारी शिक्षा भी गरीब और अमीर में बंट गयी है। मान लिया गया है कि आर्थिक अभावों से जूझ रहे परिवारों के बच्चों की विवशता है कि वे सरकारी स्कूलों में जाएं जहां पढ़ाई लगभग मुफ्त होती है। आर्थिक स्थिति जरा-सी भी सुधरती है तो यह अभिभावक महंगे स्कूलों की ओर रुख कर लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र का यह बंटवारा हमारी प्राथमिक चिंता होनी चाहिए। स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर ही विद्यार्थियों को 'छोटे-बड़े' का अहसास दिलाने वाली हमारी शिक्षा-नीति एक तरह से शिक्षा के अधिकार के हमारे दावों को ही झुठला रही है।

हम देश के हर बच्चे के शिक्षा के अधिकार की बात तो करते हैं, पर किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है इस बारे में शायद सोचना ही नहीं चाह रहे। सन् 2021-22 में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में 10,22,386 सरकारी और 3,35,844 निजी स्कूल हैं। यहां निजी स्कूल का मतलब महंगी पढ़ाई और बेहतर सुविधा है। यह कतई ज़रूरी नहीं है कि महंगी पढ़ाई का मतलब अच्छी पढ़ाई ही हो- हां, इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले अभिभावक यह अहसास अवश्य जीते हैं कि उनका स्तर 'ऊंचा' है। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के बीमार सोच का पालन उन सबके लिए चिंता की बात होनी चाहिए जो समता-समानता के दर्शन वाले संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं।

'पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया' का नारा देने वाले को इस बात की भी चिंता होनी चाहिए कि 'इंडिया' क्या पढ़ रहा है कैसी पढ़ाई कर रहा है। दुर्भाग्य से यह चिंता कहीं दिखाई नहीं देती। नीति-आयोग की इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट में हमारे स्कूलों की स्थितियों को तो अच्छे ढंग से दिखाया गया है, पर जिस तरह से यह रिपोर्ट अचर्चित ही रही है, वह हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। आखिर हमें दो तरह की शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? क्यों नहीं देश के हर बच्चे को एक समान और अच्छे स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए? इस बारे में हमारा छोटा-सा पड़ोसी देश नेपाल भी हमें कुछ सिखा सकता है।

मूल्यांकन पर आंच

अभी नीट प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्रों के लीक होने और परीक्षा रद्द होने की सुर्खियों की स्याही सूखी भी न थी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की मूल्यांकन प्रणाली सवालों के घेरे में आ गई। निश्चय ही ये घटनाक्रम छात्रों और प्रतियोगियों के परीक्षा व्यवस्था पर भरोसे को कम ही कर रहे हैं। आपदा में अवसर की तलाश में रहने वाले राजनीतिक दलों को छोड़ भी दें, तो भी आम लोग भी सीबीएसई की मूल्यांकन पद्धति पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल, सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम प्रणाली में खामियों और विसंगतियों को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं। कक्षा बारह के कुछ छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत अपलोड की गई स्कैन प्रतियों और उनकी उत्तर पुस्तिकाओं में विसंगति सामने आने का खुलासा किया है। निश्चित रूप से यह प्रकरण महज एक तकनीकी समस्या से कहीं अधिक का मामला है। यह भारत की उस शीर्ष परीक्षा प्रणाली की बढ़ती विफलता की चेतावनी है, जो लाखों छात्रों के भविष्य का निर्धारण करती है। इस घटनाक्रम में एक छात्र वेदांत श्रीवास्तव का मामला विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि सीबीएसई ने स्वयं स्वीकार किया है कि गलत उत्तर पुस्तिका भेजी गई थी। हालांकि, मामला तूल पकड़ता देख उसे बाद में सही उत्तर पुस्तिका भेज दी गई। इसी तरह एक अन्य परीक्षार्थी, संजना को भी सीबीएसई की तरफ से कमोबेश ऐसी ही प्रतिक्रिया मिली है। भला हो सोशल मीडिया का जो इन मुद्दों को देश की जनता के सामने तुरंत ले आता है और देश में इससे एक जनमत बनाने का अवसर मिलता है। हालांकि, यह स्वागत योग्य है कि सीबीएसई ने इन प्रणालीगत त्रुटियों को स्वीकार तो किया। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस लापरवाही के लिये जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अन्यथा लापरवाही व गलती का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सीबीएसई को अपनी साख बचाये रखने के लिये इस दिशा में समय रहते सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

यहां सवाल उठता है कि सीबीएसई जैसी परीक्षा नियामक संस्था ने अपने स्तर पर खामियों को दूर करने के लिये कारगर तंत्र क्यों विकसित नहीं किया। वह तब ही जागती है जब मीडिया में घटना सुर्खियां बनती है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सीबीएसई ने तब कार्रवाई की और सुधारात्मक कदम उठाये, जब प्रभावित छात्रों ने इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलाया। निश्चित रूप से एक निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली में इतना लचीलापन होना चाहिए कि छात्रों के आक्रोश के सार्वजनिक होने, राजनीतिक टीका-टिप्पणी सामने आने या ऑनलाइन अभियान चलने से पहले समस्या का निराकरण हो जाए। हालिया घटनाक्रम का एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह भी है कि सीबीएसई की लापरवाही का शिकार बने वेदांत को अपनी बात उठाने पर बुरी तरह लांछित किया। कुछ सोशल मीडिया वीरों ने उसकी मुखरता से आवाज उठाने की कोशिश को देश विरोधी तक ही नहीं कहा, बल्कि कुछ ने तो उसे पाकिस्तानी तक कह दिया। यह तंत्र के बचाव में उतरने की अंधभक्ति ही है कि न्याय के लिये आवाज उठाने के लिये पीड़ित भारतीय नागरिक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की असफल कोशिश हो। क्या न्याय के लिये आवाज उठाने वाले छात्रों को इसलिए अपमानित व प्रताड़ित होना चाहिए क्योंकि उसकी शिकायत सामने आने के बाद देश के नामचीन संगठनों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है?

विशेष आलेख /राशिफल

अदालती फैसले में खेल संघों के लिए सबक

चयन ट्रायल से महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराने के मामले में हाईकोर्ट ने अपने हालिया निर्णय से न केवल देश की एक खिलाड़ी के साथ हुए अन्याय का उचित संज्ञान लिया अपितु मातृत्व का सम्मान किया है। इससे भारतीय कुश्ती संघ की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगा है।

एशियाई खेलों के लिए कुश्ती दल के चयन ट्रायल से महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराने के मनमाने निर्णय पर उच्च न्यायालय ने भारतीय कुश्ती संघ को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने अपनी अहम टिप्पणी में कहा कि हमारे देश में मातृत्व का सम्मान किया जाता है। लेकिन भारतीय कुश्ती संघ ने तो विनेश फोगाट के मामले में अपने पुराने मानदंडों को ही बदल दिया (संभवत: व्यक्तिगत विद्वेष के चलते)। बता दें कि विनेश फोगाट ने अपनी खेल प्रतिभा से अनेक अवसरों पर भारतीयों का सिर ऊंचा किया है। हाईकोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक निर्णय से न केवल देश की इस महान खिलाड़ी के साथ हुए अन्याय का उचित संज्ञान लिया अपितु मातृत्व का सम्मान किया है और भारतीय कुश्ती संघ की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाया है। इस निर्णय के चलते भविष्य में अन्य खेल महासंघों को भी खिलाड़ियों के प्रति अन्याय करने से रोकेगा।

उल्लेखनीय है कि विनेश देश के लिए महिला कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में सर्वाधिक पदक विजेता और ओलंपिक फ़ाइनल तक पहुंचने वाली देश की एकमात्र महिला पहलवान हैं। विनेश मां बनने के बाद कुश्ती में वापसी करना चाहती थी लेकिन उसे कुश्ती संघ के नियमों के नाम पर राष्ट्रमंडलीय व एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग लेने से रोक कर

दिया गया था। कई देशों में मां बनने के बाद खेलों में लौटने की इच्छुक महिला खिलाड़ियों के लिए नियमों में छूट दी गई और उन्होंने पदक जीतकर इसे सही सिद्ध किया। लेकिन विनेश की वापसी का रास्ता बंद कर दिया गया था। विनेश के साथ-साथ देश के लाखों कुश्ती प्रेमियों के लिए यह निराशा की बात थी।

विनेश की अद्वितीय खेल उपलब्धियां भारतीय कुश्ती के लिए गर्व की बात है। विनेश ने साल 2013 में एशियाई चैंपियनशिप से पदक जीतने का सिलसिला शुरू किया। इसके साथ ही जुझारू खिलाड़ी विनेश 2022 की विश्व चैम्पियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों तक लगातार दस वर्षों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए सर्वाधिक पदक (10 स्वर्ण पदकों सहित कुल 22 पदक) जीतने में सफल रहीं। महिला पहलवान विनेश विश्व चैंपियनशिप में दो पदक, एशियाई खेलों में एक स्वर्ण सहित दो पदक और राष्ट्रमंडलीय खेलों में लगातार तीन स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की एकमात्र महिला पहलवान हैं। एशियाई चैंपियनशिप में एक स्वर्ण , तीन रजत और चार कांस्य पदकों के साथ आठ पदक जीतने वाली देश की एकमात्र पहलवान विनेश ने भारतीय कुश्ती का परचम विश्व स्तर पर फहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके दमखम और कुश्ती के प्रति अद्भुत समर्पण के विश्व भर के खेल विशेषज्ञ और खेलप्रेमी क़ायल रहे हैं। अपनी खेल प्रतिभा और उपलब्धियों के कारण विनेश को अर्जुन पुरस्कार (2016), पद्मश्री (2018) और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार (2020) व लॉरियस स्पोर्ट्स वर्ल्ड अवार्ड से नवाजा जा चुका है। 2022 और 2024 में उन्हें बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन घोषित किया गया। विनेश ने तीन ओलंपिक खेलों में महिला कुश्ती में देश का प्रतिनिधित्व किया। साल 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों में पचास किलो भार वर्ग में वह फ़ाइनल तक पहुंची। फ़ाइनल मुकाबले से पूर्व जांच में कुछ अधिक वज़न पाए जाने पर उसे अयोग्य ठहरा दिया गया। उस निराशा के चलते विनेश ने संन्यास की घोषणा कर दी थी। हरियाणा के विधानसभा चुनावों में विधायक चुने जाने और मातृत्व ग्रहण करने के बाद एक बार फिर विनेश ने कुश्ती की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने की ठानी। वह एक बार पुन: देश के लिए पदक जीतने की लालसा लिए हुए एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों के ट्रायल में भाग लेने पहुंची थी लेकिन नियमों के नाम पर उसे भाग लेने से वंचित कर पुन: निराशा में धकेल दिया गया।

क्या कहते है आपके सितारें....?

मेष आज का दिन आप के लिए एकदम शुभ है। धार्मिक काम में मन लगेगा और देव-दर्शन का लाभ मिलेंगे। विविध क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा।

सिंह किसी भी नए काम की शुरुआत आज न करें। किसी बात को लेकर मन में ग्लानि का भाव रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें। दोपहर के बाद आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार की संभावना है।

धनु आज का दिन दोस्तों के साथ मौज-मस्ती में गुजरने वाला है। मनोरंजक एक्टिविटी में आपका मन लगेगा। भागीदारी से लाभ होगा। सुखद यात्रा का संयोग बनेगा।

वृषभ परिजनों के साथ वाद-विवाद होने से मन चिंता से भरा रहेगा। छाती में दर्द या अन्य कोई शारीरिक परेशानी होने से शरीर शिथिल रहेगा। निरर्थक आर्थिक खर्च से बचें।

कन्या आज आपको विविध क्षेत्रों से लाभ होने होने की संभावना है। व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ होगा। साथी कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। दोस्तों के लिए धन खर्च कर सकते हैं।

मकर आज का दिन आपके लिए शुभ है। नौकरीपेशा लोगों का टारगेट पूरा हो सकेगा। व्यापार में लाभ मिल सकता है। पार्टनरशिप के काम सफल रहेंगे। पिता से भी आर्थिक लाभ की संभावना दिख रही है।

मिथुन आज आपको हर काम में सफलता मिलेगी। विरोधियों पर आप विजय प्राप्त कर सकेंगे। सामाजिक दृष्टि से आपको मान-सम्मान मिलेगा। दोपहर के बाद झगड़े का वातावरण बना रहेगा।

तुला आज का आपका दिन खुशी और आनंद के साथ गुजरेगा। आप कुछ अधिक ही संवेदनशील रहेंगे। आपकी कोई चिंता दूर हो सकती है। स्नेहीजन और मित्रों से मुलाकात सुखद रहेगी।

कुंभ आज सुबह आपका मन क्रोधित रहेगा। शारीरिक रूप से अस्वस्थ और मानसिक रूप से चिंता का अनुभव होगा। व्यर्थ धन खर्च होगा। विद्यार्थियों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे।

कर्क किसी बात की अशांति रहेगी। किसी कारणवश आकस्मिक धन खर्च आएगा। शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा। दोपहर के बाद घर में आनंद और शांति का वातावरण बन जाएगा।

वृश्चिक आज का दिन पूरी तरह से शुभ फलदायी है। व्यापार करने वालों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे।

मीन आज वाणी में संयम रखें। स्नेहीजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा। किसी कन्फ्यूजन में दिन गुजरेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें।

नरेंद्र मोदी से मुलाकात

महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस की पीएम मोदी से मुलाकात

नई दिल्ली (एजेंसी)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। इसके साथ ही दोनों नेताओं की फोटो भी शेयर की है। पीएमओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद बताया महाराष्ट्र के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर उनका मार्गदर्शन मिला। इसके साथ ही महाराष्ट्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज नई दिल्ली में हमारे नेता और राष्ट्र के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। महाराष्ट्र के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। मैंने उन्हें महाराष्ट्र के कई कार्यों और परियोजनाओं की प्रगति और वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने आगे लिखा, हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलना हमेशा ही प्रेरणादायक होता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

उपमुख्यमंत्री एवं राजसमंद प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने ली जिला स्तरीय समीक्षा बैठक

पानी-बिजली की आपूर्ति में कोई भी कोताही स्वीकार नहीं, समस्याओं का त्वरित समाधान हो : डॉ. बैरवा

पानी-बिजली की आपूर्ति सहित वंदे गंगा अभियान, फ्लैगशिप योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं का बारीकी से जाना हाल

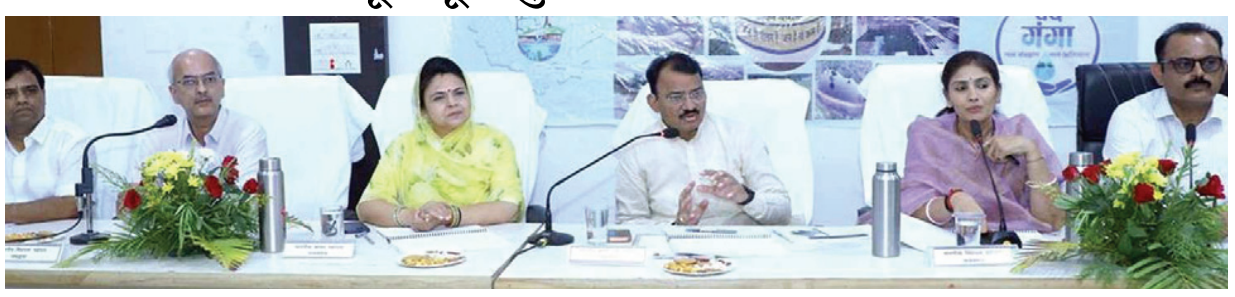

जयपुर (नि.सं.)। उपमुख्यमंत्री एवं राजसमंद प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के मुख्य आतिथ्य में गुरुवार दोपहर जिला परिषद सभागार, राजसमंद में जिला स्तरीय अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपमुख्यमंत्री डॉ बैरवा द्वारा राज्य सरकार की

विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं, समर कंटीन्जेसी प्लान, जल संचय-जन भागीदारी अभियान तथा वंदे गंगा (जल संरक्षण-जन अभियान) की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास कार्यों, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाएं तथा योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने

नवीन परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने, कुसुम योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं शहरी, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना तथा जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी ली। पंच गौरव योजना के अंतर्गत संचालित लखपति दीदी, सोलर दीदी, ड्रोन दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी एवं पशु सखी कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, अटल ज्ञान केंद्र, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं अटल प्रगति पथ सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी, मिशन हरियालो राजस्थान, अमृत योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना तथा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह

बंगाल सरकार ने बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में बीएसएफ को 600 हेक्टेयर जमीन सौंपीः अमित शाह

गांधीनगर (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में नवगठित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी के काम को मजबूत करने के लिए सात दिनों के भीतर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को 600 हेक्टेयर भूमि सौंप दी है। गांधीनगर जिले के सोनीपुर गांव में 340 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने राज्य में सीमा पर बाड़ लगाने के काम में तेजी लाने के अपने चुनावी वादे को पूरा किया है। अमित शाह ने कहा, ÷हमने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि यदि आप हमें सत्ता सौंपते हैं तो हम कुछ ही दिनों के भीतर बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर देंगे। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को बधाई देते हुए कहा, मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को महज सात दिनों के भीतर बीएसएफ को 600 हेक्टेयर भूमि सौंपने के लिए बधाई देना चाहता हूं। चिकन नेक क्षेत्र में 121 हेक्टेयर भूमि भी केंद्र सरकार को सौंप दी गई है। अमित शाह ने इस कदम को भाजपा के व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडे से जोड़ा और दावा किया कि बंगाल में सरकार परिवर्तन के बाद बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ पहले ही कम हो गई है। उन्होंने कहा, पहले ममता के शासनकाल में हर दिन घुसपैठ होती थी, लेकिन अब घुसपैठिए खुद ही वापस लौटने लगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने ये टिप्पणियां भाजपा के देश भर में बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को उजागर करते हुए कीं। उन्होंने हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को निर्णायक रूप से हराया था।

न्यूज ब्रीफ

मुख्यमंत्री का पारदर्शी सुशासन की दिशा में अहम निर्णय

राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध 4 प्रकरणों में दी अभियोजन स्वीकृति

पीएचईडी के वरिष्ठ रसायनज्ञ को सेवा से हटाने का लिया निर्णय

जयपुर(नि.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध 4 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति दी है। वहीं, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन अधिनियम, 2018) के तहत दोष सिद्धि के एक प्रकरण में आरोपित अधिकारी को सेवा से पदच्युत करने का भी अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के वरिष्ठ रसायनज्ञ को पेयजल के नमूनों की गुणवत्ता जांच में फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के अपराध में सेवा से हटाने का निर्णय लिया है।

कृषि अनुसंधान अधिकारी (कृषि विभाग) भर्ती-2024

बॉटनी के 2 एवं एग्रोनॉमी के 1 अभ्यर्थी को विस्तृत आवेदन भरने का अंतिम अवसर

जयपुर(नि.सं.)। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कृषि अनुसंधान अधिकारी (कृषि विभाग) भर्ती-2024 के अंतर्गत विचारित सूची में सम्मिलित बॉटनी के 2 तथा एग्रोनॉमी के 1 अभ्यर्थी को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरने का एक और मौका दिया है। इन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में प्रदत्त अवसरों के दौरान ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सब्मिट नहीं किया गया था। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। संबंधित अभ्यर्थी 28 मई से 1 जून 2026 (रात्रि 11:59 बजे) तक विस्तृत ऑनलाइन आवेदन सब्मिट कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।इसके बाद इस संबंध में कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में भी विस्तृत आवेदन सब्मिट नहीं करते है, तो उसे अपात्र मानते हुए चयन प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।

राज्यपाल बागडे ने कुलगुरु डॉ. देवस्वरूप को पद से हटाने के आदेश जारी किए

जयपुर(नि.सं.)। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने कुलपति पद पर रहते हुए नियुक्तियों में भारी अनियमितताएं करने, धांधलियां कर चहेते अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने और विश्वविद्यालय नियम–प्रावधानों को दरकिनार कर मनमाने तरीके से नियुक्तियां करने के मामले में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रथम कुलगुरु और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलगुरु प्रो. देवस्वरूप को अपने पद से तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश राज्य

सरकार के परामर्श से जारी किया गया है। कुलाधिपति एवं राज्यपाल बागडे को डॉ. देवस्वरूप द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए वर्ष 2011–2012 व चयन वर्ष 2013–14 के चयन में जयपुर की डॉ. प्रेमलता सिंगारिया ने अनुसूचित जाति की महिला के साथ अन्याय के अंतर्गत नियम–प्रावधानों को दरकिनार कर धांधली कर योग्य की बजाय चहेते अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की शिकायत की थी। राज्यपाल एवं कुलाधिपति ने इस पर शिक्षाविद् और कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. भगवती प्रसाद सारस्वत की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की थी। जांच समिति ने डॉ. देवस्वरूप के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की थी।

60 लाख की लागत से लगेगी 10 और हाई मास्ट लाइटें

वासुदेव देवनानी ने अजमेर के प्रमुख चौराहों पर हाई मास्ट लाइटों का किया लोकार्पण

अजमेर उत्तर में पहली बार 18 हाई मास्ट लाइटों से जगमगाएंगे प्रमुख चौराहे

जयपुर(नि.सं.)। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी के कर-कमलों द्वारा अजमेर शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित हाई मास्ट लाइटों का लोकार्पण किया गया। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में 10 हाई मास्ट लाइट लगाई जा रही हैं। इसी क्रम में बुधवार को छतरी योजना, ममता स्वीट्स वैशाली नगर एवं जवाहर रंगमंच पर हाई मास्ट लाइटों का लोकार्पण किया गया। इसी क्रम में गुरुवार को हरिभाऊ उपाध्याय नगर खेल मैदान एवं पुष्कर रोड स्थित सिटी प्राइड के सामने भी हाई मास्ट लाइट स्थापित की जाएगी। इससे पूर्व नगर निगम द्वारा भी शहर के विभिन्न स्थानों पर 8 हाई मास्ट लाइट लगाई गई थीं।

विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि पिछले दो वर्षों से अधिक के कार्यकाल में निरन्तर विकास कार्यों के

शिलान्यास एवं लोकार्पण किए जा रहे हैं। इनके परिणाम स्वरूप आज शहर परिवर्तन की नई कहानी लिख रहा है। उन्होंने कहा कि एक विधानसभा क्षेत्र में पहली बार 18 हाई मास्ट लाइट लगाई गई है। इससे प्रमुख चौराहे एवं सार्वजनिक स्थान रोशन होंगे तथा व्यापारियों, पर्यटकों एवं आमजन को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मिनी मास्ट लाइटें भी स्वीकृत की गई हैं। अजमेर उत्तर से जुड़े नवीन ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक हजार से अधिक लाइटें लगाई गई हैं। शीघ्र ही नौसर घाटी से पुष्कर रोड तक हेरिटेज लाइटें भी स्थापित की जाएंगी। इससे दीपावली पूर्व शहर पूर्ण रूप से प्रकाशमान दिखाई देगा। देवनानी ने कहा कि रोशनी के साथ मूलभूत सुविधाओं के विकास पर भी विशेष कार्य किए जा रहे हैं। अजमेर उत्तर क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए से अधिक के सड़क निर्माण कार्य कराए गए है। पुष्कर घाटी में बड़े वाहनों की आवाजाही को सुरक्षा की दृष्टि से नियंत्रित किया गया है तथा रिंग रोड के माध्यम से यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है।

डोनाल्ड ट्रम्प का जन्मदिन

ट्रम्प जन्मदिन पर व्हाइट हाउस में फाइटिंग कराएंगेः मुकाबले के लिए स्टेज तैयार हो रहा

1 लाख लोग फ्री में मुकाबला देखेंगे

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 14 जून को 80 साल के हो जाएंगे। इस मौके पर व्हाइट हाउस में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप (UFC) के मुकाबले कराए जाएंगे। खेल दुनिया की सबसे बड़ी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) संस्था है। इसमें अलग-अलग फाइटिंग खेलों के खिलाड़ी एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबला करते हैं। खेल चीफ डाना व्हाइट ने बताया कि व्हाइट हाउस में फाइट कराने का विचार खुद ट्रम्प ने दिया था। उनके मुताबिक इसके लिए व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में खास फाइटिंग एरिया बनाया जा रहा है, जहां 4 हजार से ज्यादा लोग बैठ सकेंगे। इसके अलावा व्हाइट हाउस के पास एलिप्स फील्ड में फाइट्स दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीनें लगाई जाएंगी। यहां 75 हजार से लेकर 1 लाख लोग मुफ्त में मुकाबला देख सकेंगे। व्हाइट ने बताया कि ट्रम्प चाहते थे कि यह मुकाबला अमेरिका के 250वें स्थापना वर्ष के जश्न का हिस्सा बने। अल जजीरा के मुताबिक, मुख्य मुकाबले में अमेरिकी फाइटर जस्टिन गेथजी और जॉर्जिया के स्टार फाइटर इलिया टोपूरिया आमने-सामने होंगे।

ट्रम्प 1000 टिकट बांटेंगे: डाना व्हाइट ने कहा कि उनके पास बांटने के लिए 200 टिकट होंगे,

ओमान को ट्रंप ने धमकाया, ईरान बोला हम आपके साथ खड़े हैं

तेहरान/मस्कट (एजेंसी)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कथित धमकी के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इस बयान के बाद ईरान ने ओमान के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने की बात कही है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि ईरान, अमेरिकी अधिकारियों की धमकियों के खिलाफ ओमान के साथ खड़ा है। यह प्रतिक्रिया तब आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर कहा कि यदि ओमान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण के मुद्दे पर ÷बाकी देशों की तरह व्यवहार÷ नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बाघेई ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की धमकियां क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा हैं।

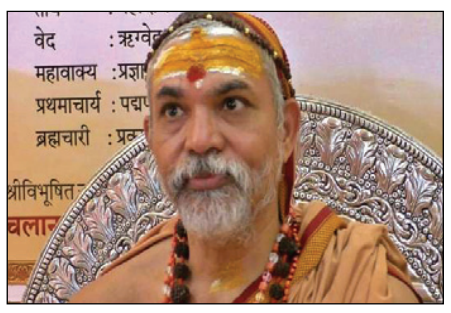

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बोले, हम गाय की रक्षा के लिए वोट देंगे

फतेहपुर (एजेंसी)। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ-रक्षा को लेकर कहा कि हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि गाय को पशु कहने वाली सरकार को हटाओ और गाय को माता कहने वाली सरकार लाओ। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि गाय की सुरक्षा को लेकर बात तो की जा रही है लेकिन उनकी गौ-भक्ति केवल मंचों और वक्तव्यों तक सीमित है। धरातल पर विपरीत स्थिति है। आश्रय स्थलों में गायों की हालत बहुत बुरी है। गौ तस्करों पर आज तक अंकुश नहीं लग पाया है। गायों के लिए कागजी काम हो रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जनता इनके प्रचार में आ जाती है।

भीषण गर्मी में मूक पशु-पक्षियों के बचाव के लिए आगे आई राज्य सरकार

जयपुर (नि.सं.)। भीषण गर्मी में आमजन विशेषकर राहगीरों के लिए पेयजल, छाया-पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ–साथ मूक पशु–पक्षियों की भी देखरेख हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस संकल्प को पूरा करने के लिए उनकी प्रेरणा से समूचा प्रशासनिक अमला जुट गया है। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में पीपल के 11 वृक्षों पर दानें और पानी के लिए परिण्डे बांधे। उन्होंने सचिवालय कैंटीन के पास स्थित बर्ड साईट पर पक्षियों के लिए दाना डाला। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा के बाद राज्यभर में यह अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य सचिव ने गत दिनों परिपत्र जारी कर सभी जिला कलेक्टर, स्थानीय निकाय एवं संबंधित विभागों को ग्रीष्मकाल के दौरान पशु-पक्षियों को तेज गर्मी एवं लू से बचाने तथा उनके लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

मुख्य सचिव ने परिण्डे बांधने के बाद कहा कि गर्मी में प्राकृतिक जल स्त्रोतों के सूखने के कारण पशु-पक्षियों के लिए पेयजल उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण है, ऐसे में हम सभी को इन मूक प्राणियों के लिए गर्मी के मौसम में पेयजल, छाया और दाने की व्यवस्था के लिए संवेदनशीलता के साथ प्रयास करना चाहिए।

वर्ल्ड ब्लड कैंसर डे **नई तकनीकों से ब्लड कैंसर का इलाज संभव**

वर्ल्ड ब्लड कैंसर डे पर डॉक्टर ने कहा-बार-बार बुखार, खून की कमी के लक्षण को नहीं करें इग्नोर

जयपुर(नि.सं.)। अगर इलाज के बाद भी आपको बार-बार बुखार आ रहा है। शरीर में कमजोरी आ रही है। शरीर में खून की कमी है। हाथ-पांव में कमजोरी महसूस हो रही है, तो इन लक्षणें को इग्नोर नहीं करें। अगर इलाज के बाद भी ये लक्षण ठीक नहीं हों तो ये ब्लड में कैंसर सेल की शुरुआत का अलर्ट हो सकता है। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल (बीएमसीएच) के ब्लड कैंसर और बीएमटी विशेषज्ञ डॉ. प्रकाश सिंह शेखावत ने यह बात कही। आज वर्ल्ड ब्लड कैंसर डे है। इस पर डॉ.

शेखावत ने बताया- कार-टी सेल थैरेपी और बोनमैरो ट्रांसप्लांट (बीएमटी) जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से ब्लड कैंसर और ब्लड से जुड़ी दूसरी गंभीर बीमारियों के इलाज हो रहे हैं। इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं।

नई तकनीकों में ऐसे होता है इलाज

डॉ. प्रकाश सिंह शेखावत ने बताया- कार-टी सेल थैरेपी में मरीज की प्रतिरक्षा कोशिकाओं (टी-सेल) को विशेष तकनीक से कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर नष्ट करने के लिए तैयार किया जाता है। वहीं बीएमटी के जरिए रोगग्रस्त बोनमैरो को स्वस्थ स्टेम सेल्स से रिप्लेस किया जाता है। यह इलाज ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल मायलोमा, थैलेसीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया जैसे गंभीर रोगों में उपयोगी है। पीडियाट्रिक ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ. शिवानी माथुर ने बताया- बच्चों में कई तरह के ब्लड कैंसर होते हैं।

शुरुआती स्तर में इसका इलाज करके इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। उन्होंने बताया- बीएमसीएच में ब्लड कैंसर से जुड़ी दो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके तहत रोगियों का फ्री इलाज किया जाता है। ये बच्चों के लिए जीवनदान परियोजना है।

डिजिटल रणक्षेत्र में भाटी का 'एकछत्र राज': त्रिकोणीय मुकाबले के नायकों को छोड़ा पीछे

रविंद्र भाटी की आक्रामक रणनीति, बैकफुट पर पारंपरिक राजनीति !

खेताराम बृजवाल। बाड़मेर

पश्चिमी राजस्थान की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में जमीनी जंग के साथ-साथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी वर्चस्व की जंग तेज हो गई है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सोशल मीडिया पर अपनी लोकप्रियता का लोहा मनवाते हुए क्षेत्र के पारंपरिक राजनीतिक दिग्गजों को काफी पीछे छोड़ दिया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, भाटी की ऑनलाइन फैन फॉलोइंग ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी और सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल को पछाड़कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। मारवाड़ के सियासी अखाड़े में भले ही हरीश चौधरी और कैलाश चौधरी पारंपरिक राजनीति के बड़े चेहरे माने जाते हैं, लेकिन डिजिटल युग की नई और आक्रामक फैन फॉलोइंग के मामले में युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी इस समय मारवाड़ की राजनीति में सबसे आगे चल रहे हैं। भाटी की इस तेज़ी से बढ़ती लोकप्रियता ने मारवाड़ के पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। जहां हरीश चौधरी और कैलाश चौधरी जैसे नेता दशकों के सांगठनिक अनुभव और दलीय व्यवस्था के भरोसे राजनीति करते हैं, वहीं भाटी की ताकत उनका सीधा जनसंवाद और डिजिटल प्रभाव है। पारंपरिक राजनीति के स्थापित चेहरों के मुकाबले शिव से विधायक भाटी सोशल मीडिया और युवाओं के बीच एक अभूतपूर्व 'इंटरनेट संसेशन' बनकर उभरे हैं।

युवाओं में बढ़ा क्रेज, मिनटों में वायरल हो रहे वीडियो -

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स (ट्विटर) पर रविंद्र सिंह भाटी के फॉलोअर्स की संख्या में अभूतपूर्व उछाल आया है। उनकी जनसभाओं के वीडियो और रील अपलोड होते ही कुछ ही मिनटों में लाखों व्यूज पार कर रहे हैं। गूगल और यूट्यूब सर्च ट्रेंड में भी भाटी बाकी तीनों नेताओं के मुकाबले काफी आगे चल रहे हैं।

स्थानीय समीकरण: जातिगत और पारंपरिक गढ़ों में डिजिटल सेंधमारी -

बाड़मेर-जैसलमेर और बालोतरा का इलाका हमेशा से पारंपरिक और जातिगत समीकरणों (विशेषकर जाट-राजपूत और अल्पसंख्यक गठजोड़) के इर्द-गिर्द घूमता रहा है। हरीश चौधरी और उम्मेदाराम बेनीवाल जहां अपनी पार्टी कैडर और मजबूत जातिगत आधार के सहारे राजनीति करते हैं, वहीं कैलाश चौधरी भाजपा के संगठनात्मक ऊंचे कद का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने इस पारंपरिक समीकरण की सीमाओं को सोशल मीडिया के जरिए तोड़ दिया है। उन्होंने जातिगत दीवारों से परे जाकर जैसलमेर के दूर-दराज के सरहदी गांवों से लेकर बाड़मेर के शहरी युवाओं तक अपनी सीधी पहुंच बनाई है। भाटी की यह डिजिटल ताकत जमीन पर भी युवाओं को उनके पाले में खींचने का बड़ा जरिया बन रही है, जो इस पूरे रेगिस्तानी बेल्ट के पारंपरिक वोट बैंक को हिलाने की क्षमता रखती है।

बिरादरी के दिग्गजों पर भी भारी पड़े भाटी -

मारवाड़ और विशेषकर बाड़मेर-जैसलमेर की राजनीति में राजपूत समाज का हमेशा से बड़ा राजनीतिक प्रभाव रहा है। इस मरुधरा ने सूबे को कई बड़े और कद्दावर राजपूत चेहरे दिए हैं। लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल लोकप्रियता के मामले में रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी ही बिरादरी के कई स्थापित और पारंपरिक राजपूत नेताओं को बहुत पीछे छोड़ दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जहां समाज के अन्य बड़े और वरिष्ठ राजपूत नेता अभी भी पारंपरिक संगठन, वीआईपी कल्चर और तय ढर्रे की राजनीति तक सीमित हैं, वहीं भाटी ने अपनी आक्रामक शैली और 'यूथ अपील' के दम पर समाज के युवाओं को पूरी तरह अपने पाले में कर लिया है।

इन चार रणनीतियों से दिग्गजों को किया 'फिसड्डी' :

'रिएक्शन टाइम' में सबसे आगे : बासनपीर छतरियां विवाद या ओरण बचाओ आंदोलन जैसा कोई भी स्थानीय मुद्दा हो, भाटी की रणनीति तुरंत ग्राउंड जीरो पर पहुंचने और लाइव आकर माहौल को अपने पक्ष में करने की होती है। दूसरी तरफ, हरीश चौधरी और कैलाश चौधरी जैसे नेता पहले अपनी पार्टियों (कांग्रेस/भाजपा) के आलाकमान के रुख और बयानों की समीक्षा करते हैं। इस देरी के कारण वे जनता के बीच 'रिएक्टिव' (प्रतिक्रियावादी) नजर आते हैं, जबकि भाटी 'प्रोएक्टिव' बनकर पूरी लाइमलाइट बटोर लेते हैं।

पारंपरिक वोट बैंक के ढर्रे को तोड़ना: हरीश चौधरी और कैलाश चौधरी मारवाड़ के मजबूत जातीय और पार्टी आधारित वोट बैंक के पारंपरिक गणित पर निर्भर रहते हैं। इसके उलट, रविंद्र सिंह भाटी की रणनीति जातियों के बंधनों को दरकिनार कर सीधे 'युवा वर्ग' को एक अलग सॉलिड वोट बैंक में तब्दील करने की है। यह रणनीति चुनावों में दोनों बड़े दलों के कैडर वोट बैंक में भारी सेंधमारी करने में कामयाब रही है।

सोशल मीडिया को हथियार बनाना : दोनों दिग्गज नेता सोशल मीडिया को सिर्फ एक सूचना देने वाले (इंफॉर्मेटिव) प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करते हैं। वहीं, भाटी की कोर रणनीति सोशल मीडिया को एक 'इमोशनल और नैरेटिव बिल्डर' (माहौल बनाने वाले) हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की है। उनकी रैलियों की रील्स और तीखे संवाद युवाओं में एक 'एंटी-एस्टेब्लिशमेंट' (व्यवस्था विरोधी) नायक की छवि गढ़ते हैं, जिसका मुकाबला करने में पारंपरिक नेताओं की आईटी टीमें फेल साबित हो रही हैं।

दलगत दबाव से मुक्ति : कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता होने के नाते हरीश चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री के रूप में कैलाश चौधरी पार्टी की गाइडलाइंस से बंधे रहते हैं। वे कई बार स्थानीय जनता की आक्रामकता के साथ खड़े नहीं हो पाते। दूसरी तरफ, निर्दलीय होने के कारण भाटी पर ऐसा कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। वे किसी भी मुद्दे पर सीधा और बेबाक स्टैंड लेकर जनता के साथ खड़े हो जाते हैं, जिससे पारंपरिक राजनीति के चेहरों की स्थिति उनके सामने फीकी पड़ जाती है।

बेबाक अंदाज और सीधा जुड़ाव बना जीत का मंत्र -

भाटी की इस बढ़ती लोकप्रियता के पीछे उनका ठेठ देसी अंदाज, बेबाक भाषण शैली और युवाओं से सीधा संवाद है। जहां कैलाश चौधरी, हरीश चौधरी और उम्मेदाराम बेनीवाल अपनी बात रखने के लिए पारंपरिक माध्यमों पर निर्भर हैं, वहीं भाटी ने डिजिटल स्पेस को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। स्थानीय जनसमस्याओं, पानी, बिजली और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने जैसे मुद्दों को तुरंत सोशल मीडिया पर उठाना उन्हें इस रेस में सबसे आगे बनाए हुए है।

डिजिटल युग बनाम पारंपरिक सियासत -

मारवाड़ की राजनीतिक जमीन पर इस समय एक बड़ा पीढ़ीगत और तकनीकी बदलाव देखा जा रहा है। एक तरफ जहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी (पूर्व राजस्व मंत्री) और भाजपा के कैलाश चौधरी (पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री) दशकों के सांगठनिक अनुभव, दलीय कैडर और चुनावी गणित के दम पर राजनीति करते हैं, वहीं दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी का पूरा तंत्र युवाओं की 'आक्रामक डिजिटल आर्मी' पर टिका है।

जैसा अंदाज, वैसी आक्रामक फैन फॉलोइंग -

रविंद्र सिंह भाटी के पास सोशल मीडिया पर मारवाड़ के किसी भी अन्य नेता से कई गुना अधिक फॉलोअर्स हैं, जो उनकी डिजिटल ताकत को प्रमाणित करते हैं। उनके बढ़ते सियासी रसूख को नीचे दिए सोशल मीडिया के आंकड़ों से समझ सकते है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

इंस्टाग्राम
रविंद्र सिंह भाटी - 30 लाख (3.0रू)
हरीश चौधरी -2.5 लाख
कैलाश चौधरी -4.1 लाख

फेसबुक
रविंद्र सिंह भाटी - 24 लाख (2.4रू)
हरीश चौधरी - 8.1 लाख
कैलाश चौधरी - 12 लाख

एक्स
रविंद्र सिंह भाटी - 11 लाख (1.1रू)
हरीश चौधरी - 4.9 लाख
कैलाश चौधरी - 4.8 लाख

प्रवासी राजस्थानियों में भी भाटी का क्रेज -

प्रवासी राजस्थानियों के बीच रविंद्र सिंह भाटी का क्रेज इस कदर हावी है कि सात समंदर पार और देश के कोने-कोने में बसे मारवाड़ी युवा उनके एक बुलावे पर अपनी मातृभूमि की ओर खिंचे चले आते हैं। पारंपरिक राजनेताओं के विपरीत, भाटी ने प्रवासी नेटवर्क को केवल चुनावी चंदे का जरिया नहीं बनाया, बल्कि उन्हें मारवाड़ की राजनीति में एक निर्णायक 'वोट बैंक' और 'डिजिटल एम्बेस्डर' के रूप में खड़ा कर दिया है। दुबई, कुवैत, मस्कट और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों मारवाड़ी श्रमिकों और व्यापारियों के बीच भाटी की लोकप्रियता शीर्ष पर है। वहां से युवाओं द्वारा भाटी के समर्थन में बनाए गए रील्स और वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं। गुजरात (अहमदाबाद, सूरत), महाराष्ट्र (मुंबई, पुणे), कर्नाटक (बेंगलुरु) और तमिलनाडु जैसे राज्यों में व्यापार कर रहे प्रवासियों के बीच भाटी ने सीधे संवाद कार्यक्रम किए। उनके इन दौरों में उमड़ी भारी भीड़ ने बड़े-बड़े राष्ट्रीय नेताओं को चौंका दिया था।

न्यूज इन बॉक्स

मुख्य सचिव पहुंचे पुलिस मुख्यालय, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 और R4C की व्यवस्थाओं को परखा

जयपुर(नि.सं.)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास गुरुवार को पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने साइबर अपराध नियंत्रण एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की कार्यप्रणाली को लेकर उच्चस्तरीय बैठक ली। इस दौरान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और अतिरिक्त मुख्य सचिव(गृह) भास्कर ए.सावंत का स्वागत किया। बैठक में साइबर अपराधों की समीक्षा मुख्य सचिव ने राजकीय अवकाश के दिन ढाई घंटे से अधिक समय देकर साइबर क्राइम सेल की संरचना एवं कार्यविधि तथा साइबर हेल्पलाइन 1930 के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। साथ ही राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन भी प्रदान किया। मुख्य सचिव ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 के संचालन, कॉल रिस्पॉन्स सिस्टम एवं साइबर अपराधों की जांच प्रक्रिया की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन 1930 को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाया जाए तथा इसके लिए अगले 30 दिनों में विस्तृत पॉलिसी प्लान के इम्प्लीमेंटेशन का लक्ष्य निर्धारित कर कार्यवाही की जावे।

पुलिस आयुक्त ने दक्षिण जिले की कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण को लेकर की समीक्षा बैठक

जयपुर(नि.सं.)। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने शहर में बेहतर कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाने तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास एवं अपराधियों में भय की भावना स्थापित करने के उद्देश्य से गुरुवार को आयुक्तालय के दक्षिण जिले की समीक्षा बैठक की। बैठक में स्पेशल पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश,पुलिस उपायुक्त दक्षिण राजर्षि सहित दक्षिण जिले के सहायक पुलिस उपायुक्त मौजूद रहे।

महिला सुरक्षा एवं एससी-एसटी प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश

पुलिस आयुक्त श्री मित्तल ने महिला अत्याचार, बाल अपराध एवं एससी-एसटी एक्ट से संबंधित प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मामलों में पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाना पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में चोरी एवं संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी निगरानी एवं विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने तैयारियों की समीक्षा की,10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य

पूर्व के वर्षों में लगाये गये पौधों की जीवित्तता भी हो सुनिश्चित:श्रीनिवास

'मिशन हरियालो राजस्थान' को जन-आंदोलन बनाने के निर्देश

- हरियालो ऐप से होगी पौधों की जियो-टैगिंग और पूर्व में लगाये गये पौधों की पुष्टि
- 29 विभागों ने 10.81 करोड़ पौधों के रोपण की कार्ययोजना प्रस्तुत की

जयपुर(नि.सं.)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में मिशन हरियालो राजस्थान की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में मानसून 2026 के दौरान प्रदेशभर में किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों एवं पूर्व वर्षों में लगाए गए पौधों के सत्यापन कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि सभी विभाग लगाए गए पौधों की जीवित्तता को भी सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में भी पौधारोपण को प्राथमिकता से करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि मानसून 2024 में 7.22 करोड़ तथा मानसून 2025 में 11.75 करोड़ से अधिक पौधारोपण कर राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। आगामी मानसून 2026 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पौधारोपण के साथ पौधों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए हरियालो ऐप के माध्यम से पौधों की जियो-टैगिंग एवं लाइव फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। साथ ही मुख्य सचिव ने हरियालो राजस्थान वेबपोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नियमित मॉनिटरिंग व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए।

टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सप्लाई का प्रशिक्षण दिया

अधिशासी अभियंताओं को टीसीओएस का प्रशिक्षण

जयपुर(नि.सं.)। जयपुर डिस्कॉम के अधिशासी अभियंताओं (ओ एंड एम) को जयपुर स्थित विद्युत भवन में टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सप्लाई (टीसीओएस) का प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य अभियंता (मुख्यालय) वाई. के. ऐरन, अधीक्षण अभियंता (कमर्शियल) पी. सी. सिंघल तथा सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता पी. के. गुप्ता ने अभियंताओं को 150 किलोवॉट तक विद्युत भार वाले विद्युत कनेक्शनों को फिक्स चार्जेज के आधार पर जारी करने, 33 केवी तक के विद्युत कनेक्शनों के स्व प्रमाणीकरण के लिए जारी नई गाइडलाइन, ड्यूअल सोर्स ऑफ सप्लाई कनेक्शन जारी करने, औद्योगिक क्षेत्रों, टाउनशिप तथा मल्टीस्टोरी बिल्डिंग के विद्युतीकरण, निगम स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (CGRF), अपीलीय प्राधिकरण आदि के संबंध में प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण से डिस्कॉम के अभियंताओं को फील्ड में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं को दूर करने और नए नियमों के तहत उपभोक्ताओं को त्वरित, पारदर्शी एवं सुगमता से सेवाएं देने में मदद मिलेगी।

करौली में वीर सावरकर जयंती पर युवा सम्मेलन

माय भारत केंद्र ने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को किया सम्मानित

करौली(वि.सं.)। करौली में माय भारत केंद्र, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में वीणा मेमोरियल कॉलेज में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती पर एक युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्विज, पोस्टर और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज प्रिंसिपल मनोज शर्मा, माय भारत के उपनिदेशक पंकज यादव और संकाय सदस्यों ने वीर सावरकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। इस दौरान वक्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में वीर सावरकर के महत्वपूर्ण योगदान और उनके संघर्षपूर्ण जीवन पर प्रकाश डाला।

बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा

पर्यटन विभाग की शासन सचिव ने बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा

जयपुर(नि.सं.)। शुचि त्यागी की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग, देवस्थान विभाग एवं कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग से संबंधित वर्ष 2024-25, 2025-26 तथा 2026-27 की समस्त बजट घोषणाओं की प्रगति की कार्यकारी एजेन्सीवार समीक्षा की गई। त्यागी ने निर्देश दिए कि सभी बजट घोषणाओं को समय पर गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सोमवार को केंद्रीय प्रवर्तित प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। जिन कार्यों को एक से अधिक एजेंसियों के द्वारा संपादित किया जा रहा है ऐसे कार्यों कि एजेंसियां आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिए कि दोहराव वाली बजट घोषणाओं का औचित्यपूर्ण परीक्षण करवाकर निस्तारण किया जाए। शासन सचिव ने सभी कार्यकारी एजेंसीज एवं देवस्थान, पर्यटन, कला साहित्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे चल रहे विकास कार्यों का मौके पर जाकर भी निरीक्षण करें।

आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में किया सरेंडर

पहले आश्रम पहुंचा, फिर एम्स में जांच करवाई, एयरपोर्ट पर समर्थकों दिया आशीर्वाद

जोधपुर(वि.सं.)। आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद वह गुरुवार को जोधपुर पहुंचा। दोपहर 2:50 बजे आसाराम के आने की सूचना पर जोधपुर एयरपोर्ट पर उसके समर्थकों की भीड़ लग गई। आसाराम ने भी गाड़ी से समर्थकों को आशीर्वाद दिया। आसाराम एयरपोर्ट से सीधे पाल गांव स्थित अपने आश्रम पहुंचा। वहां से एम्स गया, जांच करवाने के बाद शाम करीब 5 बजे सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया। दरअसल, बुधवार को हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए अंतरिम जमानत रद्द कर दी थी।

[illegible]